

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरडक, आर०ए०एस०

अपील संख्या 32/2019

1-भंवरदान पुत्र पूसदान जाति चारण निवासी गिरधारीपुरा तहसील लाडनूं जिला
नागौर राज०

.....अपीलान्ट

बनाम

1-तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज०।

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री मो० अली शेरानी व महावीर प्रजापत अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956


अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार लाडनूं मु०सं० 08/2018 बअनुवान सरकार
जरिये हल्का पटवारी, ध्यावा बनाम भंवरदान अन्तर्गत धारा 91 भू०राजस्व अधिनियम
निर्णय दिनांक 11.04.2019

निर्णय

दिनांक:08.02.21

{1} -मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ध्यावा द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध तहसीलदार लाडनूं को एक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने मौजा ग्राम गिरधारीपुरा के खसरा नम्बर 15 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै०मु० मुमकिन चारागाह भूमि पर पक्की दीवार बनाकर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से वेदखल करने का निवेदन करने पर तथा पटवारी हल्का ध्यावा व भू०अ०नि० सारङ्गी की जाच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार लाडनूं द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 7.02.2018 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। अप्रार्थी को जरिये सम्मन अन्तर्गत 91 एल०आर.एक्ट 1956 के




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

तहत तलब किया गया। नोटिस बाद तामिल स्वयं अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हुं। अप्रार्थी नै दिनांक 30.05.18 को मय अधिवक्ता उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 151सी.पी.सी. वास्ते सीमाज्ञान पेश किया, जिसकी जाँच सीमाज्ञान भूअ0निरीक्षक सारडी से करवाया गया। सीमाज्ञान के आदेश की पालना रिपोर्ट भूअ0निरीक्षक सारडी ने पेश कर जाहिर किया कि मौके पर खसरा नम्बर 15 गै0मु0 गौचर पर अतिक्रमण पाया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.04.2019 को निर्णय कर अप्रार्थी को खसरा नम्बर 15 रकवा 0.02 बीघा किस्म गै0 मु0 चारागाह पर अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी से वेदखल करने के आदेश पारित किये गये तथा वार्षिक लगान 0.30 रूपये के 50 गुणा से रूपये 2/- अक्षर दौ रूपये मात्र जुर्माना आरोपित किया गया।


उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील दिनांक 10.06.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्त की अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार के प्रकरण संख्या 08/18 सरकार बनाम भंवरदान जाति चारण में निर्णय की सत्यापित फोटोप्रति अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम दिनांक 7.02.2018 से 11.04.2019 की सत्यापित प्रति, पटवारी हल्का ध्यावा की मौका रिपोर्ट, व जमाबन्दी की सत्य प्रति पेश की है।

[2] –वकील अपीलान्त की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्त ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:-

[2](1) –यह है कि निर्णय जैर अपील तहसीलदार लाडनूं कानूनन वाकियातन एवं विधि के सामान्य सिद्धान्तो तथा विधि के प्रावधान के विरुद्ध होने से सही नहीं है एवम निरस्त किया जाने योग्य है।

2 – यह है कि अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 30.05.2018 को उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कया गया था कि खसरा नम्बर 15 गै0 मु0 चारागाह का सीमाज्ञान करवाया जावें ताकि यह स्पष्ट हो जावें क खसरा नम्बर 15 पर किसने अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डी.जी.

लाडनू ने भू0अ0निरीक्षक को मौका जाँच का आदेश दिया तथा सीमाज्ञान नही करवाया, जिससे भी निर्णय अपील निरस्त किया जाने योग्य है।

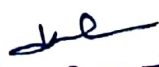
{2}(3) – यह है कि भू0अ0निरीक्षक सारङ्गी ने दिनांक 11.04.2019 को मौका रिपोर्ट पेश की, वह सही नहीं है। भू-अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट में लिखा है कि खसरा नम्बर 15 की सीमा ज्ञान का नाप करना अंकित पाया पाया तथा अप्रार्थी का खसरा नं0 15 पर गैर मुमकिन गौचर में अतिक्रमण है। जबकि भू0अ0नि0 सारङ्गी ने सीमाज्ञान नाप की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। जिससे निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाने योग्य हैं।

{2}(4) – यह है कि खेत खसरा नम्बर 28 वाके सरहद गिरधारीपुरा का अप्रार्थी/अपीलार्थी खातेदार काश्तकार है व कब्जा काश्त अपीलार्थी का है, जिसके चिपते ही खसरा नम्बर 15 गै0 मु0 चारागाह की भूमि है खसरा नम्बर 15 के चारों भूजाओं का क्या क्या नाप है, मौके पर खसरा नम्बर 15 की कितनी भूमि है तथा कितनी भूमि कम है एवम किस दिशा की भूजा कम पड़ रहीं है, तथा अतिक्रमी की भूमि मौके पर कितनी कम या ज्यादा है, बिना सीमाज्ञान के नहीं कहा जा सकता है कि किसने अतिक्रमण किया है। अतः बिना नाप सीमाज्ञान के पटवारी उक्त भूमि पर कैसे अतिक्रमण बता सकता है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त करने योग्य है।

{2}(5) – यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को जवाब का अवसर नहीं दिया गया। अप्रार्थी का जवाब लिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त योग्य है।

{2}(6) – यह है कि हल्का पटवारी ध्यावा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक ने साक्ष्य में पेश नही हुये है, जिस कारण अप्रार्थी को अपना पक्ष साबित करने के लिये जिरह का अवसर नही मिला है तथा अप्रार्थी को अपना साक्ष्य पेश करने का भी अवसर नहीं दिया गया है, जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त योग्य है।




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना


{2}(7) – यह है कि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि में बाड़ा मकान व होद ग्राम गिरधारीपुरा की आबादी भूमि में बना हुआ हैं, जिसके पक्की चार दीवारी बनी हुई हैं। जो उसके स्वयं की खातेदारी भूमि हैं। अप्रार्थी ने खसरा नं० 15 की सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने गांव के चन्द लोगों की द्वेषतावतश की गई झुठी शिकायत पर गलत रिपोर्ट पेश की है।

{2}(8) – यह है कि अप्रार्थी ने यह भी बताया कि अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधान की पालना नहीं कि है, तथा अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया गया है, जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त करने योग्य है।

{2}(9) – यह है कि अपीलार्थी को उक्त निर्णय दिनांक 11.04.2019 को अप्रार्थी की अनुपस्थिति में सुनाया गया है। तथा अप्रार्थी को निर्णय की जानकारी भू-अभिलेख निरीक्षक के बताने पर हुई तथा दिनांक 04.06.2019 को निर्णय की नकले लेने पर जानकारी हुई।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का ध्यावा की रिपोर्ट व भू०अ०निरीक्षक सारडी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी ग्राम गिरधारीपुरा खसरा नम्बर 15 कुल रकबा 5.17 बिघा गै० मु० चारागाह में से 0.02 बीघा किस्म गै०मु० रास्ता पर पक्की दीवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखली तथा वार्षिक लगान दर 0.30 रुपये का 50 गुणा 2/- अक्षरे दो रुपये जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के विरुद्ध जो नोटिस जारी किया वो विधिवतरूप तामिल हुवे हैं, तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.03.2018 पर स्वयं अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। अपीलान्त ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी के विरुद्ध की गई 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही बिना जाँच के विधि विरुद्ध की गयी है। जबकी विचारण न्यायालय कि पत्रावली दिनांक 11.04.2019 की आदेशिका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीमाज्ञान किया गया हैं तथा भू०अ०निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट से अप्रार्थी का अतिक्रमण होना पाया गया है, तथा अधिनरथ ने जवाब हेतु समय देने के उपरान्त भी




अतिरिक्त जिला कलक्टर
लुडियाना

सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिससे यह सावित होता है कि अप्रार्थी को जवाब हेतु समय दिया गया है, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थी ने जवाब के साथ भी ऐसा कोई साक्ष्य सवूत पेश नहीं किया जिससे सावित होता हो कि उसका उक्त मुतनाजा भूमि पर कब्जा नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर देकर विधि अनुरूप निर्णय किया गया है। तथा पटवारी हल्का ध्यावा व भू-अभिलेख सारङ्गी की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से सावित होता है कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर अतिक्रमण है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0म0 चारागाह की भूमि जो राजकीय भूमि है, पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि में आती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

∴ आ दे श ∴

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है।


अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.04.2019 यथावत रखा जाता है।




निर्णय आज दिनांक: 08.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा

से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।




(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (राजस्थान)


(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (राजस्थान)